IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शैक्षणिक प्रभाव मूल्यांकन

सौरभ शुक्ला[1] and डॉ. सचिन कुमार प्रभाकर[2]

अनुसंधान विद्वान, विभाग -शिक्षा[1]

शोध निर्देशक, विभाग -शिक्षा[2]

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सार

हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) में अनुच्छेद 45 के संबंध में एक निर्देश है, जिसमें कहा गया है कि सभी को शिक्षा के लिए समान रूप से सुलभ होना चाहिए। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य को केंद्र के निर्देश का पालन करना होगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अब 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कई नए शैक्षिक हस्तक्षेप किए हैं जैसे कि मिड-डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा में पारंपरिक स्कूली शिक्षा पैटर्न में बदलाव लाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसलिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हासिल करने के लिए पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 34 साल पुरानी है, की जगह ले रही है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास 2030 एजेंडा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को आवश्यक लचीलेपन के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली में बदल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहु-विषयक पहलू छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक कदम होगा।

शब्दकोश:- नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

परिचय :

नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 तक प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें शिक्षा छोड़ चुके छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए शिक्षा की धारा में वापस लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। पाठ्यक्रम 5+3+3+4 शर्तों में तैयार किया

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

गया है, यानी बारह साल की स्कूली शिक्षा और तीन साल की आंगनवाड़ी। बुनियादी फाउंडेशन शिक्षा और संख्यात्मकता पर शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच का अंतर बहुत कम हो गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा 6 से शुरू करने की योजना है। ग्रेड 5 तक मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। पारंपरिक जांच की तुलना में व्यापक विश्लेषण के साथ छात्र की प्रगति को बेहतर समग्र तरीके से ट्रैक किया जाता है। कई लचीले विषयों के साथ उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात में लगभग 50% की वृद्धि होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा प्राधिकरण को चार अलग-अलग विंगों द्वारा समर्थित किया जाना है, जिनके संबंधित कार्यों की निगरानी की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण के साथ स्वायत्त कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता दी जानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गैर-पहुंच वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के लिए लिंग और विशेष क्षेत्रों के आधार पर धन शामिल करने के तरीके भी शामिल हैं। प्रौद्योगिकी के समावेश पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा मंचों की शुरुआत की गई है।

विद्यालय शिक्षा

माना जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा पूरी करने के कई तरीके प्रदान करके शिक्षा बीच में ही छोड़ देने वाले छात्रों को वापस लाएगी। अनुमान है कि लगभग दो करोड़ ड्रॉपआउट छात्र मुख्यधारा की शिक्षा में वापस आएँगे। नीति परामर्शदाताओं के सहयोग से अनौपचारिक शिक्षा के लिए भी प्रावधान करती है; यह जीवन संवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और वयस्क साक्षरता को भी बढ़ाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बचपन की शिक्षा, पारंपरिक 10वीं और +2 संरचनाओं को 5+3+3+4 संरचना में बदलने पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। आयु के संबंध में नई स्कूली शिक्षा संरचना को 3 वर्ष से 8 वर्ष, 8 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 14 वर्ष और 14 वर्ष से 18 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। संज्ञानात्मक मानसिक कौशल 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के दौरान बहुत विकसित होते हैं; इस आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक संरचना के बराबर शामिल किया गया है। नई शिक्षा में 3 साल की आंगनवाड़ी है, जो एक उल्लेखनीय घटना है। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के छात्रों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। आंगनवाड़ी और प्री-स्कूलों के लिए एक समावेशी रणनीति विकसित करने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को बढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीतियों का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

साक्षरता और संख्यात्मक

प्राथमिक विद्यालय से ही संख्यात्मकता के संबंध में आधारभूत साक्षरता समय की मांग है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 के माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करता है। यह उम्मीद की जाती है कि राज्य राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन के निर्माण के साथ-साथ 2025 तक अपने-अपने राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के दिशा-निर्देशों को लागू करेंगे। शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने में 21वीं सदी के विकास को अच्छी तरह से शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का फोकस आलोचनात्मक सोच के माध्यम से प्रयोगात्मक शिक्षा है। इसलिए छात्रों को विज्ञान और कला के संबंध में सीखने में विषय विकल्पों के संबंध में लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए।

बहुभाष्यता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संख्यात्मकता के अलावा एक और विशेषता है जो भाषा है, नीति छात्रों को बहु-भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक तीन भाषा रणनीतियों के लिए एक विकल्प प्रदान करती है, जहाँ छात्र अपनी इच्छानुसार भाषा पाठ्यक्रम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। छत्र योजना "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के तहत छात्रों को भारत में भाषाओं के संबंध में प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय भाषाओं की तुलना में विदेशी भाषा को द्वितीयक प्राथमिकता दी जाती है। श्रवण बाधित छात्रों को भारतीय सांकेतिक भाषा की सुविधा दी जाती है, जिसे पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।

उल्लेखनीय सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करती है; ये परीक्षाएँ नियमित मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती हैं। नियमित मूल्यांकन छात्रों के कौशल के साथ-साथ उनके विषयों के संबंध में उनकी रुचि को भी दर्शाता है। बोर्ड परीक्षाएँ पारंपरिक तरीके से होंगी, जो 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है, लेकिन सुधारित तरीके से। समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र बाल शिक्षा में गहरी रुचि रखती है, जहाँ कोई भी बच्चा शिक्षा से पीछे न रहे। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह जो लिंग, सामाजिक पहलुओं और भौगोलिक पहलुओं पर आधारित हैं, उन्हें कमज़ोर किया जाएगा। विकलांग छात्रों के

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

लिए कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, जहाँ वे प्राथमिक शिक्षा से लेकर सभी स्कूली शिक्षा प्रक्रिया तक पहुँच सकते हैं और उन्हें आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। बाल भवन की अवधारणा, जो बच्चों के लिए एक डेकेयर है, सभी जिलों में स्थापित की जाएगी। बाल भवन, विशेष रूप से सामाजिक चेतना केन्द्र कहे जाने वाले निःशुल्क स्कूल परिसरों में, विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर कला उन्मुख गतिविधियों को समृद्ध बनाने में मदद करेंगे।

सुदृढ़ शासन

नई शिक्षा नीति के तहत चयन समय-समय पर बहु-स्रोत प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों की स्थापना शुरू करेगी। शैक्षणिक परिसरों को समूहों में विभाजित किया जाएगा जो बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सरकार के परिसर के रूप में कार्य करेंगे। नीति निर्माण और अन्य परिचालन नियमों के एक अलग कार्य की निगरानी एक स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के माध्यम से की जाएगी। स्कूलों की गुणवत्ता का आकलन स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और मान्यता ढांचे के साथ-साथ अन्य हितधारकों द्वारा किया जाएगा।

बहुविषयक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतःविषय पहलू को प्रोत्साहित करती है, जिसमें विषयों के संबंध में विभिन्न विकल्प हैं। नीतियों के माध्यम से उपयुक्त प्रमाणन के साथ-साथ बहु-प्रवेश और निकास की अवधारणा को पेश किया गया है। उदाहरण के लिए, 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम को एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, दो वर्षीय उन्नत डिप्लोमा, तीन वर्षीय स्नातक डिग्री और शोध कार्यक्रम के साथ चार वर्षीय स्नातक में वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्च शिक्षण संस्थान से प्राप्त क्रेडिट को अकादमिक बैंक क्रेडिट नामक एक तंत्र में संग्रहीत किया जाता है, जहाँ क्रेडिट को स्थानांतरित किया जा सकता है। नीति वैश्विक मानकों के साथ बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी दर्शाती है। अनुसंधान मंच की निगरानी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नामक एक शीर्ष निकाय द्वारा की जाएगी। मेडिकल और कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर, अन्य सभी पाठ्यक्रमों को भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। शीर्ष निकाय में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा ग्रैंड काउंसिल और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद जैसे विभिन्न विंग होंगे। मुख्य बिंदु यह है कि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

के हर चरण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों के लिए मानदंडों का एक समान सेट तैयार किया जाएगा।

मार्गदर्शन विजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान को एक उच्च मान्यता प्राप्त संगठन में बदलना है, जिसमें शिक्षण और शोध की परिकल्पना की गई हो। संबद्धता प्राप्त करने के लिए, कॉलेजों को प्रशासन के आधार पर तंत्र के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वायत्त या सरकारी कॉलेज हैं। NCTE प्राधिकरण शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसलिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता चार वर्षीय एकीकृत बी.एड डिग्री होगी। परामर्श या सलाह देने का एक तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्त संकाय छात्रों के लिए अल्पावधि या दीर्घकालिक अवधि में संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए ऐसा तंत्र न केवल छात्रों को पढ़ाई छोड़ने से रोकेगा बल्कि उन्हें उपयुक्त करियर की ओर भी मार्गदर्शन करेगा।

छात्रों के लिए सहायता

सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों को शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और इसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग भी शिक्षा की सेवा का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाल ही में की गई पहल के अनुसार MOOC प्लेटफॉर्म के डोमेन से ऑनलाइन पाठ्यक्रम पारंपरिक शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना उसमें मूल्य जोड़ते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा विकल्प है जो निश्चित रूप से कोविड जैसी परिस्थितियों के दौरान छात्रों का समर्थन करेगा जहां कोई ऑनलाइन के माध्यम से घर पर रहकर सीख सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम नामक एक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान का आयोजन किया गया है। छात्रों के लाभ के लिए विदेशी शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करके शिक्षा में वैश्वीकरण का लाभ उठाया जाएगा

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

चार विशिष्ट विशेषताएँ

पहली विशेषता है नया शिक्षा पैटर्न जो 5+3+3+4 है यह पैटर्न की 10+2 प्रणाली थी। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लचीलापन। फिल्म पाठ्यक्रम में कई लचीली सुविधाओं के साथ आई है जिसे छात्र पाठ्यक्रम पैटर्न के संबंध में अपनी रुचि के अनुसार चुन सकता है। बिना सुविधा के वह घटना है जहां कॉलेज या विश्वविद्यालय अद्वितीय खुफिया मंच प्रदान करते हैं जहां संकाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सभी छात्रों के शिक्षाविदों के साथ-साथ पाठ्येतर गतिविधियों के प्रदर्शन रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। चौथा मानदंड या विशेषता चुनौतीपूर्ण कार्य है जो आने वाले लचीले पाठ्यक्रम के लिए तैयारी कर रहा है। यह खेल सुविधा या शिक्षा के अगले युग की आधारशिला है इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में बदलाव देखने के लिए परिवर्तनों का स्वागत करना आवश्यक है।

प्रमुख चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हितधारकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन चुनौतियाँ हैं। यहाँ हम चुनौतियों को चरण दर चरण देखेंगे:

छात्रों के अभिभावकों के लिए चुनौती

अभिभावकों के पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कोई विचार नहीं है। नीति को अत्यंत महत्व के साथ तैयार किया गया है; फिर भी अभिभावकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में स्पष्ट विचार बनाने में कठिनाई होती है। यह प्रबंधन शिक्षा के संबंध में भी बहुत हद तक सच है। यह स्पष्ट रूप से पीढ़ी एक्स को पीढ़ी वाई और आने वाली पीढ़ी से अलग करता है। कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में, अभिभावकों को वर्तमान में अपनाई जा रही ऑनलाइन शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो एक आघात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों की शिक्षा के संबंध में अभिभावकों के सामने एक चुनौती बन गई है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में लचीलापन

दूसरी चुनौती राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में लचीलापन है, छात्रों के पास पहले से ही लचीला पाठ्यक्रम है, फिर भी छात्रों ने पिछले युग में ऐसा लचीलापन कभी नहीं देखा है। इसलिए सभी छात्रों के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है, खासकर उन छात्रों के संबंध में जो गाँव या ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों या छात्रों के साथ, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में लचीलेपन को समझना अधिक कठिन लगता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

उन्हें क्रेडिट कोर्स के बारे में भी पता नहीं है कि यह उन्हें डिग्री कोर्स या ब्रिज कोर्स या पोस्ट-ग्रेजुएशन आदि प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा। प्रबंधन पाठ्यक्रमों के दृष्टिकोण से छात्र लचीले पाठ्यक्रम और बाजार की वास्तविक समय की आवश्यकता के बीच कनेक्टिविटी के बारे में वास्तव में चिंतित हैं। छात्र बाजार के स्टेशनों के बारे में लगभग चिंतित हैं। मौजूदा बाजार पारंपरिक पाठ्यक्रमों पर आधारित है जो पहले प्रचलित थे लेकिन वर्तमान परिदृश्य ने शिक्षा पैटर्न में बहुत सारे बदलाव लाए हैं।

चुनौती बाजार के खिलाड़ियों के साथ है तीसरी चुनौती निजी कंपनियों और सरकारी कंपनियों के संबंध में बाजार के खिलाड़ियों के साथ है, वे ही हैं जो छात्रों को नौकरी देते हैं। कंपनियाँ आमतौर पर पारंपरिक पैटर्न का पालन करती हैं जहाँ वे सही लोगों की तलाश करती हैं या योग्यता के आधार पर कर्मचारियों का चयन करती हैं। शिक्षा पारंपरिक शैक्षिक पैटर्न पर आधारित थी, वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने न केवल स्कूली शिक्षा के पैटर्न के संबंध में बल्कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ भी प्रचलित पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है। अब समय की मांग है कि निजी कंपनियों के साथ-साथ सरकारी कंपनियों को भी नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर अपनी भर्ती नीतियों को बदलना होगा। यह एक आसान काम नहीं है, उन्हें अंततः सही नौकरी की आवश्यकताओं के लिए उन्हें भर्ती करने के लिए सही योग्यता वाले सही लोगों को ढूंढना होगा। इसलिए निजी और सरकारी दोनों भर्तीकर्ताओं को आवश्यक भर्ती नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गहन विश्लेषण करना होगा।

ग्रे क्षेत्रों के संबंध में कुछ चुनौतियाँ

अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दूरस्थ शिक्षा पैटर्न को लगभग दुविधा में डाल दिया है। पारंपरिक दूरस्थ शिक्षा पैटर्न को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, दूरस्थ शिक्षा में प्रबंधन पाठ्यक्रमों के संबंध में ग्रे क्षेत्र पाए जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा में बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। अब प्रबंधन शिक्षा पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा के संबंध में नई शिक्षा नीति के साथ-साथ चलना होगा। यह शिक्षाविदों और छात्रों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों के लिए जो दूरस्थ शिक्षा से सबसे अधिक लाभकारी शेयरधारक थे।

ग्रेडिंग पैटर्न के संबंध में चुनौती

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में एक और प्रमुख चुनौती ग्रेडिंग पैटर्न है। ग्रेडिंग पैटर्न अब बहुत अधिक लचीलेपन के साथ आने वाला है। पाठ्यक्रम के संबंध में छात्रों के लिए ग्रेडिंग पैटर्न एक कठिन कार्य बन गया है। चूंकि

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

छात्रों को शिक्षा के संबंध में चुनने के लिए विभिन्न क्षेत्र प्रदान किए जाते हैं, इसलिए संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए छात्र के ऐच्छिक के आधार पर ग्रेड देना भी मुश्किल हो जाता है। प्रबंधन संस्थान के संबंध में यह बहुत हद तक सही है क्योंकि प्रबंधन संस्थानों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम या ऐच्छिक के संबंध में विभिन्न क्षेत्र होते हैं। प्रबंधन संस्थान में, छात्रों के पास बाजार में मौजूद प्रॉस्पेक्टस की विभिन्न विशेषताओं को चुनने की क्षमता होती है। इसलिए छात्र अपने पहले से मौजूद पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे ऐच्छिक पा सकते हैं। इसलिए ग्रेडिंग पैटर्न में एकरूपता लगातार बदलावों के संबंध में एक चुनौती है। इसलिए सभी छात्रों के संबंध में समान ग्रेडिंग पैटर्न बनाना मुश्किल हो जाएगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के गुण स्कूली शिक्षा से लेकर पोस्ट-डॉक्टरल शोध अध्ययन और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तक व्यापक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने संस्थानों का स्व-मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शन और अनुमति देती है। नीति मौजूदा असमानताओं और संरचना में व्याप्त अन्य शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। हालाँकि नीति में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी पहलू हैं, फिर भी व्यावहारिक कार्यान्वयन समय की माँग है। कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग और चुनौतीपूर्ण नीति का समर्थन करने के लिए सभी राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। पूरे देश के लिए एकल प्राधिकरण, जो कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद है, राज्यों और राज्य शिक्षा परिषदों की शक्ति को कमज़ोर करता है। धन के संबंध में, नीति कार्यान्वयन पूरी तरह से सरकार के धन पर निर्भर करता है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 6% है, जो वर्तमान परिदृश्य में फिर से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए, सभी मौजूदा चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन समय की एकमात्र आवश्यकता है।

संदर्भ

[1]. एम. (2020). एनईपी 2020: नई शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी मंच के गठन पर विचार किया गया।

[2]. जयन, टी.वी. (2020). राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देगा।

[3]. मसौदा पैनल प्रमुख ने कहा कि नई शिक्षा नीति में कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। https://www.indiatoday.in/education/story/no-language-imposition-new- education-policy-drafting-panel-chief-1705975-2020-07-30 से लिया गया।

[4]. पंडित, ए. (2020). लिंग समावेशन निधि, नीति में विशेष शिक्षा क्षेत्र।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, April 2024

https://timesofindia.indiatimes.com/india/gender-inclusion-fund-spl-edu-zones-in policy/articleshow/77252728.cms#:~:text=NEW%20DELHI%3A%20In%20what%20op ens,as%20well%20as%20transgender%20students से लिया गया।

[5]. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण एनईपी पर आधारित: नीति 'क्या सोचना है' से ध्यान हटाकर 'कैसे सोचना है' पर केंद्रित होगी। https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/pm-narendra-modi-speech-live-new-education-policy-inaugural-education-conclave-1708665-2020-08-07 से लिया गया।

[6]. शुक्ला, ए. (2019)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। https://www.hindustantimes.com/education/hrd-begins-process- for-creation-of-national-research-foundation/story-W37ngkZmNkw6cSYZlXTlIL.html से लिया गया।

[7]. शुक्ला, ए. (2020)। सरकार ने शिक्षा के लिए व्यापक बदलावों की घोषणा की। https:// education/story-zSewHWq7IiCaOOLNXUiRcK.html से लिया गया।

[8]. सकल नामांकन अनुपात में सुधार के लिए, नई शिक्षा नीति अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रस्ताव करती है; कई प्रवेश, निकास बिंदु। https://www.news18.com/news/india/to-improve-gross-enrolment-ratio-new-education-policy-proposes-academic-bank-of-credit-multiple-entry-exit-points- 2742693.html से लिया गया।

[9]. यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से छात्रों, शिक्षकों के बीच नई शिक्षा नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने को कहा। https://www.hindustantimes.com/education/ugc-ask-varsities-to-create-awareness-about-new-education-policy-among-students-teachers/story-XjDXDw978SXD0VUPUmxhvL.html से लिया गया।

[10]. उपाध्याय, डी. (2020)। नई स्कूल शिक्षा नीति को मंजूरी: ग्रेडिंग सिस्टम, विषयों के अधिक विकल्प। https://www.livemint.com/education/news/new-school-education-policy-grading-system-more-choice-of-subjects-11596001769379.html से लिया गया.